RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 02 FEBRUARY 2022 TO 08 FEBRUARY 2022 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 22 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जनवरी में कच्चा तेल 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा, क्या होगा पेट्रोल और डीजल पर असर Page 2

बजट के बाद वे 10 बातें जो एक ग्राहक को जाननी चाहिए Page 4

अनंत सेवा फाउंडेशन का प्रोजेक्ट डिग्निटी 2.0 ग्रामीण क्षेत्रों के 1000 गरीब परिवारों की करता है मदद Page 7

editoria!

ग्रोथ का बजट

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए यह आम सोच थी कि बजट लोकलुभावन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सोच को गलत साबित किया है। बजट का फोकस सरकारी खर्च बढ़ाकर आर्थिक विकास दर तेज करने पर है, जिसकी जरूरत भी थी। इसलिए यह ग्रोथ का बजट है, बोल्ड बजट है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इससे महंगाई दर बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 फीसदी रखा है, जो इससे पिछले साल में 6.8 फीसदी रहा। यह भी ठीक है। अभी आर्थिक रिकवरी को मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति के जरिये वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने का एलान किया। यह भी अच्छा कदम है। सरकार कुछ समय से पीएलआई स्कीम के जरिये 14 क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। यह आत्मनिर्भर भारत के अजेंडा के साथ निर्यात बढ़ाने में भी कारगर हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत के अजेंडा को सरकार ने आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने बजट में क्रिप्टोकरंसी पर भी निवेशकों की उलझन दूर कर दी। उन्होंने इससे हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। वित्त वर्ष 2023 में रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी लाएगा, इसका ऐलान भी निर्मला सीतारमण ने किया। इन दोनों बातों से लगता है कि सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को एक एसेट तो मान लिया है, लेकिन वह इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसे, अगर इसमें राहत दी गई होती तो उससे खपत बढ़ाने में मदद मिलती। खासतौर पर यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में मध्य वर्ग की आय में भी कमी आई है और आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। यहां तक कि समृद्ध तबके को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर सरचार्ज घटाकर राहत दी गई है। निम्न-मध्यम आय वर्ग के लिए हाउसिंग सेक्टर में सौगात दी गई है। कृषि क्षेत्र के लिए एमएसपी पर रेकॉर्ड खरीद की बात वित्त मंत्री ने की, लेकिन किसी और राहत का एलान नहीं किया। विनिवेश के लिए भी लक्ष्य 65 हजार करोड़ का ही रखा गया है, जो कम है, लेकिन इस मामले में सरकार के खराब रेकॉर्ड को देखते हुए ठीक लगता है। वित्त मंत्री ने इस मामले में यह जरूर कहा कि कुछ महीनों में एलआईसी का आईपीओ आएगा। इधर, रोजगार का मुद्दा भी राजनीतिक रंग ले रहा है। इस मामले में बजट को देखकर लगता है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद कर रही है। कुल मिलाकर, सरकार ने बजट के साथ एक रिस्क लिया है। देखना होगा कि यह कैसा रिटर्न देता है।

सरकार ने खोला खजाना

बुनियादी ढांचे के विकास के जरिये बढ़ेगा भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये खजाना खोलते हुए 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से राजमार्गों से लेकर सस्ते मकानों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।

वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है। लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया। साथ ही सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिये रियायती दर की समयसीमा बढ़ाने के साथ डिजिटल मुद्रा शुरू करने तथा क्रिप्टो संपत्तियों पर कर लगाने के भी प्रस्ताव किये हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी बजट में बुनियादी ढांचा खर्च पर अच्छा-खासा जोर है। इसमें 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, नदियों को जोड़ने की योजना तथा नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तेज वृद्धि के लिये आधार रखने का संकल्प जताते हुए कहा, ''अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना और पुनरुद्धार हमारे देश की मजबूती को बताता है।''उन्होंने कहा, ''बजट में राजकोषीय मजबूती की जगह आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दी गयी है। बजट वृद्धि के लिये निरंतर गति प्रदान करता रहेगा।''

बजट 2022 की वे छोटी-मोटी राहत

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया।
- राज्य सरकार के एंप्लोई भी एनपीएस में वेतन के 14 फ़ीसदी तक के योगदान पर डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे।
- कोविड-19 से मौत होने पर मिला मुआवजा भी रू. 10 लाख तक की रकम पर तक नॉन टैक्सेबल होगा।
- करदाता टैक्स रिटर्न को अपडेट करने के लिए 3 साल की मदद ले सकते हैं और अतिरिक्त टैक्स चुका सकते हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रस्ताव किया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से मिला पैसा टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा।
- सेंट्रल बैंक के डिजिटल करंसी से डिजिटल इकॉनमी को काफी बल मिलेगा। यह डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करंसी है, उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेगी।
- अब भारत में डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा

उद्योगों को पंजीयन में मदद करेगा मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्लास्टिक उद्योगपतियों के साथ आनलाइन मिटिंग में बोले अधिकारी

दूषित जल शोधन के लिए दी जरूरी जानकारी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग कारखानों से निकलने वाले पानी को ट्रीट कर के ही बार छोड जाए। सभी उद्योग का मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीयन हो और उनके द्वारा हवा, पानी के प्रदूषण को रोकने में सहयोग किया जाए। इसके लिए मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगपतियों को पुरी मदद करेगा। यह बात मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी श्री संजय जैन ने उद्योगपतियों से आनलाइन जूम मिटिंग के दौरान कही। उन्होनें कहा कि शासन की योजना विवाद से विश्वास के तहत उद्योग अपने स्व घोषणा पत्र के माध्यम से पानी और हवा के प्रदूषण की जानकारी दे सकते है। दूषित जल को पहले ट्रीट करने के बाद ही छोडा जाए इसके लिए भी जरूरी कार्यवाही की जाना जरूरी है।

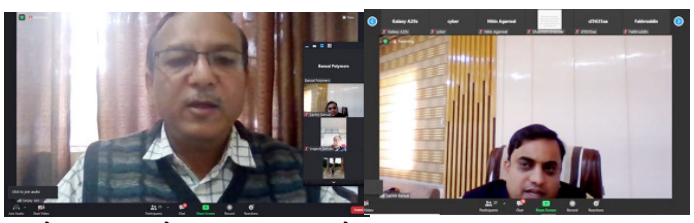

प्रदेश के प्लास्टिक उद्योगों के सबसे बडे संगठन इंडियन प्लास्ट पैक फोरम द्वारा आयोजित इस बैठक में बडी संख्या में उद्योगपतियों और निर्माताओं ने भाग लिया। संगठन के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि आनलाइन मिटिंग के दौरान उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं और सुझावों के माध्यम से जानकारी ली। इस दौरान मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी श्री जैन ने अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए किसी भी परेशानी के लिए सीधे बात करने की बात कही। उन्होनें बताया कि बीते दिनों संयुक्त कार्यवाही में कई उद्योगों को सील करने की कार्यवाही की गई थी। ऐसी स्थिती से बचने के लिए सभी उद्योपतियों से मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीयन करवाने में संगठन स्तर पर भी हर संभव मदद की जा रही है। श्री बंसल ने बताया कि इस दौरान वरिष्ठ उद्योगपतिय श्री सुभाष चतुर्वेदी, श्री हितेश मेहता, श्री प्रमोद सोमानी, ब्रजेश गांधी सहित बडी संख्या में उद्योगपतियों ने मिटिंग में हिस्सा लिया।

कस्टम ड्यूटी में आए बदलाव

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर। देश के बजट में वित्तमंत्री द्वारा कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन की घोषणा की गई थी। संबधित प्रमुख प्लास्टिक उत्पादों के लिए सीमा शुल्क में बदलाव आए है।

CUSTOM DUTY CHANGES IN BUDGET

Chemicals	From	To
Naphtha	10.0%	2.5%
Caprolactam	10.0%	5.0%
Sodium polyacrylate	10.0%	5.0%
Plastics in primary forms (except polymers of vinyl chloride , polyamides)	10.0%	7.5%
Sorbitol	30.0%	20.0%
Acrylonitrile	10.0%	2.5%
Styrene	10.0%	2.0%
Purified Terephthalic Acid	10.0%	5.0%
Mono ethylene glycol	10.0%	5.0%
Vinyl chloride monomer	10.0%	2.0%
Ethylene Dichloride	10.0%	Free
Halogenated, Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons	10.0%	5.0%
Ortho/Para xylene	10.0%	Free
Calcined Petroleum Coke	10.0%	7.5%
Pitch and pitch coke	10.0%	5.0%
Ethyl alcohol	30.0%	5.0%
Acetic acid	10.0%	5.0%
Methanol	10.0%	2.5%

जनवरी में कच्चा तेल 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा, क्या होगा पेट्रोल और डीजल पर असर

नई दिल्ली। एजेंसी

साल 2022 के पहले महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली हैं और पहली फरवरी को हल्की गिरावट से पहले ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया. ऐसे में सरकारी खजाने पर कीमतों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. हालांकि बीते करीब 3 महीने से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में आशंका बन रही है कि आने वाले समय में कीमतों में एक बार फिर बढ़त का सिलसिला शुरू हो सकता है. इससे पहले दिवाली के करीब सरकार ने तेल कीमतों में कटौती का तोहफा दिया था, जिसके बाद से तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

जनवरी में 17 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ क्रूड

जनवरी के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड 77.78 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 91.21 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया यानि इसमें 17.26 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है. भारत की क्रूड बास्केट में ब्रेंट क्रूड की प्रमुख हिस्सेदारी होती है. हालांकि फरवरी के पहले दिन क्रूड में गिरावट दर्ज हुई लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड 88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर है. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव की वजह से देखने को मिली है. फिलहाल रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने हैं वहीं यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं इससे आशंका बन गई है कि रूस यूरोपीय देशों के लिये तेल की सप्लाई बाधित कर सकता है. रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है. वहीं अन्य तेल उत्पादक देश भी बढ़ती मांग के अनुसार सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं जिससे मांग के मुकाबले सप्लाई पर असर

की आशंका बन गई है और तेल कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है, गोल्डमैन पहले ही आशंका जता चुका है कि इस साल ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर छू सकता है, इसके लिये मांग में तेज उछाल के मुकाबले सीमित सप्लाई को वजह बताया गया है.

क्या हो सकता है पेट्रोल और डीजल पर असर

घरेलू बाजारों में पिछले करीब 90 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बीच तेल की कीमतों में बढ़त से तेल कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलने लगा है. पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के अनुसार भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत 26 जनवरी को 88.23 डॉलर प्रति बैरल थी. पीपीएसी के अनुसार, यह आंकड़ा अक्टूबर, 2021 में 74.85 डॉलर प्रति बैरल, नवंबर में 74.47 डॉलर प्रति बैरल और दिसंबर में 75.34 डॉलर प्रति बैरल था. वहीं एनालिस्ट अनुमान जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर चिंतायें घटने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहेगी. हालांकि मीडिया में अनुमान दिया जा रहा है कि विधान सभा चुनावों की वजह से सरकार फिलहाल बढ़ोतरी से बचना चाहेगी.पीटीआई ने उद्योग सूत्रों के हवाले से लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे और इससे पहले ईंधन की कीमतों में वृद्धि की संभावना नहीं है

ओपेक बैठक से पहले तेल कीमतों में तेजी

जानिए क्या है उम्मीद

नई दिल्ली। एजेंसी

25वीं ओपेक + बैठक से पहले बुधवार को कच्चे तेल की कीमतें चढ़ गईं। सुबह 9:40 बजे, ब्रेंट क्रूड 0.28% बढ़कर 89.41 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था और यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड मंगलवार को फ्लैट बंद होने के बाद 0.24% चढ़कर 88.41 डॉलर पर पहुंच गया। लाभ के साथ, तेल की कीमतें पिछले सप्ताह शुक्रवार को अपने सात साल के उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं, जिसमें ब्रेंट ₹ 91.7 / बैरल और यूएस क्रूड ₹ 88.84 / बैरल की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस साल अब तक, तंग वैश्विक आपूर्ति और यूरोप और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है, और उन्होंने सकारात्मक नोट पर फरवरी की शुरुआत की है। निर्धारित बैठक में, ओपेक ₹ को मध्यम उत्पादन वृद्धि की मौजूदा नीतियों से चिपके रहने की उम्मीद है, और यह तर्क देते हुए तेजी से वृद्धि से परहेज करने से इनकार कर दिया है कि उपभोग करने वाले देशों द्वारा हरित ईंधन के लिए खराब गणना की गई ऊर्जा संक्रमण के कारण दुनिया ऊर्जा की कमी का सामना कर रही है, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इस बीच, पांच सूत्रों ने उच्च तेल की कीमतों के बावजूद मार्च में 4 लाख बैरल / दिन की योजनाबद्ध वृद्धि के साथ बैठक को आगे बढ़ाने की पुष्टि की है। इसके अलावा, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल और प्राकृतिक गैस की कीमतें भी कई साल के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही हैं।

बजट के अगले दिन 477 अंक तेजी के साथ खुला Sensex

नई दिल्ली। एजेंसी

आज बजट के अगले दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। आज बीएसई का सेंसेक्स करीब 477.28 अंक की तेजी के साथ 59339.85 अंक के स्तर पर खुला। वहीं एनएसई का निफ्टी 135.00 अंक की तेजी के साथ 17711.80 अंक के स्तर पर खुला। आज बीएसई में शुरुआत में कुल 1,565 कंपनियों में ट्रेडिंग शुरू हुई, इसमें से करीब 1,029 शेयर तेजी के साथ और 462 गिरावट के साथ खुलीं। वहीं 74 कंपनियों के

शेयर के दाम बिना घटे या बढ़े खुले। इसके अलावा आज 73 शेयर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और 4 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं 135 शेयर में सुबह से ही अपर सर्किट लगा है और 158 शेयर में लोअर सर्किट लगा है। निफ्टी के टॉप गेनर आईटीसी का शेयर करीब 5 रुपये की तेजी के साथ 232.45 रुपये के स्तर पर खुला। पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन का शेयर करीब 4 रुपये की तेजी के साथ 216.80 रुपये के स्तर पर खुला। बजाज फिनांस का शेयर करीब 136 रुपये की तेजी के साथ 7,151.00 रुपये के स्तर पर खुला। कोटक महिन्द्रा का शेयर करीब 38 रुपये की तेजी के साथ 1,919.80 रुपये के स्तर पर खुला। आयशर मोटर्स का शेयर करीब 43 रुपये की तेजी के साथ 2,665.30 रुपये के स्तर पर खुला।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे चढ़ा

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे चढ़कर 74.71 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.76 पर खुला और बाद में 74.71 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। इससे पहले मंगलवार को रुपया डॉलर के

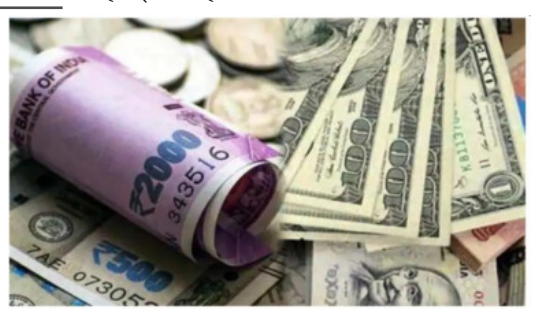

मुकाबले 17 पैसे की गिरावट लेकर 74.82 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 96.26 पर था। रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ अनुसंधान विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि डॉलर की कमजोरी से सरकार के कमजोर राजकोषीय घाटे के अनुमानों की भरपाई हो सकती है। वही वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.34 प्रतिशत बढ़कर 89.46 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

Budget 2022: आखिर बजट को चुनाव से क्यों रखा गया दूर

नई दिल्ली। एजेंसी

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को लोकलुभावन नहीं रखा। आम तौर पर चुनावी मौसम में सरकारें बजट को लोकलुभावन रखती हैं लेकिन वित्त मंत्री ने बजट को मुफ्त उपहारों और वादों से दूर रखा है। हालांकि, बजट में कई सारी ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिससे आने वाले वक्त में रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञ इसे रिस्की बजट भी बता रहे हैं।

2024 चुनाव से पहले होंगे बड़े ऐलान?

लोकलुभावन बजट पेश नहीं करने के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मान रहे हैं कि देश की जनता उनके 'न्यू इंडिया' के आइडिया को स्वीकार करेगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि सरकार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फायर पावर बचाकर रखना चाहती है। इससे पहले बजट के बाद पत्रकारों से बात में निर्मला ने कहा था कि पीएम ने टैक्स नहीं बढ़ाने को कहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट पर पीएम के मन की बात का जरूर ध्यान रखा गया है।

विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

आम तौर पर पहले बजट को विकास बढ़ाने के लिए एक खाका माना जाता था। इस बार का बजट पहले की तुलना में बेहतर करता दिख रहा है। सरकार ने इस बजट में काफी पैसे का जुगाड़ किया है और इस बात की पूरी तैयारी है कि जिस मद पैसे जाए वहां उसे खर्च किया जाए। ऐसे में पूंजगत व्यय में बढ़ोतरी का फैसला नौकरी बढ़ने पर दिख सकता है। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कनेक्टिविटी पर खर्च के प्रस्ताव से विदेशी निवेश हो सकता है क्योंकि कोरोना महामारी में सप्लाई चेन पर काफी असर पड़ा था। ऐसे में बेहतर कनेक्टिविटी पर प्रस्ताव भविष्य की योजना को दर्शाता है।

ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण पर जोर के क्या मायने?

बजट में ग्रीन और पर्यावरण बचाने पर जोर को रोजगार के अवसर से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर्स पर बजट में प्रस्ताव को भविष्य को रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट को 'अमृत काल' के रूप में अगले 25 साल का विजन पेश किया गया है जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा।

गांव पर भी जोर

बजट में ग्रामीण इलाकों की स्थिति को भी ठीक करने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण वोटर्स ने कुकिंग गैस, फ्री हाउस और अच्छी सड़क के नाम पर बीजेपी को समर्थन दिया था। इस बार के बजट में मुफ्त आवास, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर और गांवों में नल से जल की योजनाओं को और आगे ले जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा गांवों में बिजली और बेहतर संपर्क को लेकर भी तैयारी है। सरकार ने छोटे और मझोले उद्योग के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कई सारे ऐलान किए हैं। निश्चित तौर पर इन प्रस्ताव से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पीएम मोदी ने की थी बजट की तारीफ

पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, हर नल में जल आए, उनके पास शौचालय हो और गैस की व्यवस्था हो। इन सभी पर विशेष ध्यान देते हुए यह बजट बनाया है। साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है। हिमालय के पूरे पट्टे पर भी जीवन आसान बनाने और वहां से पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणाएं की गई हैं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है। इससे पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

Budget 2022

अब गांवों में भी बनेंगी शहरों जैसी पक्की सड़कें! सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार 1 फरवरी को देश की संसद में पेश किए गए आम बजट में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़ी पीएमजीएसवाई योजना के लिए वर्ष 2022-23 में आवंटन पिछले साल के राजस्व अनुमान से 36 फीसदी बढ़ाकर 19 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन लगभग 11 प्रतिशत कम कर दिया गया है। मनरेगा सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल आवंटन वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वित्त वर्ष के 1,53,558.07 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर अब 1,35,944.29 करोड़ रुपये ही रह गया। यानि, इसमें सीधे-सीधे करीब 18 हजार करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है।

36 फीसदी बढ़ाया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट

वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए आवंटन संशोधित अनुमान 14,000 करोड़ रुपये से 36 प्रतिशत बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है, लिहाजा मंगलवार को पेश बजट में ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के इन दोनों घटकों के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।

अन्य प्रमुख निर्माण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए भी बजट आवंटन ढाई फीसदी बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2021-22 में 19,500 करोड़ रुपये था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना सहित कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया आत्मनिर्भर भारत का बजट

बताते चलें कि संसद में बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने बजट की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, 'आज का आत्मनिर्भर भारत का बजट हमारे देश के विकास पथ में नई ऊर्जा और ताकत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब हम साहसपूर्वक वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक रोजगार लेकर आया है। वहीं दूसरी ओर, विपक्षी पार्टियों ने इस बजट पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बजट में नौकरीपेशा को नहीं मिली कोई राहत

जानिए फिर भी कैसे 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर बचाएं पूरा टैक्स!

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट से नौकरीपेशा की उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में सभी नौकरीपेशा करदाता निराश हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें तो 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं। अधिकतर लोग टैक्स बचाने के बारे में आखिर वक्त में सोचते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का खेल नहीं हैं। इसके लिए आपको साल शुरू होने के साथ-साथ प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सैलरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, सारे एग्जेम्पशन और डिडक्शन होते हैं तो यकीनन आप 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि आपको 12 लाख रुपये की सैलरी तक पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।

बजट के बाद वे 10 बातें जो एक ग्राहक को जाननी चाहिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की। लेकिन साथ ही कई चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ गया है। तराशे हुए हीरों, आयातित ब्लैंकेट्स, रुमाल और ओवरकोट जहां सस्ते हुए हैं वहीं विदेशी छाते, विदेशी मछली और हैडफोन्स के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। यहां देखिए पूरी लिस्ट..

वित्त मंत्री ने कट और पॉलिश किए हुए हीरों और जवाहरात पर सीमा शुल्क घटाने की घोषणा की है। पहले इन पर 7.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगती है जिसे घटाकर अब पांच फीसदी करने का प्रस्ताव है। यानी अब हीरा और जेमस्टोन खरीदना सस्ते हो जाएंगे। अब 1,30,000 रुपये की आधा कैरेट सॉलिटेयर डायमंड रिंग पर आपको 2,500 रुपये की बचत होगी।

इमिटेशन ज्वेलरी हुई महंगी

आयातित इमिटेशन ज्वेलरी पहनने के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20 परसेंट या 400 किलो पर किलो, जो भी अधिक हो, करने की घोषणा की है। यानी अगर आप गोवा को बाजार से 1000 रुपये की एक किलो इम्पोर्टेड इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 250 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

विदेशी छाता हुआ महंगा

अगर आप धूप और बारिश से बचने के लिए विदेशी छाता इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपके ज्यादा पैसा चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने इस पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। यानी अब आपको Loyzo ब्रांड के इम्पोर्टेड छाते के लिए 1,199 रुपये के बजाय 1290 रुपये चुकाने होंगे।

हेल्दी लाइफस्टाइल हुआ महंगा

कोरोना काल में हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी अब आपको ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। 250 ग्राम Tassyam Turkish हेजलनट्स के लिए अब आपको 449 रुपये के बजाय 515 रुपये चुकाने होंगे। बजट में आयातित हेजलनट्स पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का प्रस्ताव है। हेजलनट एक जड़ी-बूटी है, जिसे कोबनट या फिल्बर्ट नट भी कहा जाता है।

विदेशी मछली पर खर्च बढ़ा

खाने की शौकीनों के लिए भी इस बजट में अच्छी खबर नहीं है। वित्त मंत्री ने अटलांटिक सैलमन मछली पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। इससे 450 ग्राम मछली के लिए अब आपको 265 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। अब इसकी कीमत बढ़कर 1795 रुपये जाएगी। यह मछली फाइबर से भरपूर होती है, जो वजन को नियंत्रण करने में हेल्प भी कर सकती हैं।

हींग का तड़का लगाना हुआ सस्ता

भारतीय व्यंजनों में हींग का व्यापक इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्री ने हींग के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। इसे 20 फीसदी के घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। 10 ग्राम अफगान हींग पर अब आपको 50 रुपये सस्ती मिलेगी। अब तक इसकी कीमत 495 रुपये थी। भारत में हींग का ज्यादातर आयात अफगानिस्तान से ही होता है।

म्यूजिक सुनना हुआ महंगा

म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनने के लिए अब देश के लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैडफोन्स पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। अब AKG Y500 हैडफोन्स पर आपको 9,314 रुपये चुकाने होंगे जबकि अब तक इसकी कीमत 8,999 रुपये थी। यानी 315 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

विदेशी रुमाल भी हुए सस्ते

वित्त मंत्री ने विदेशी रुमाल पर भी कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। इन पर अब 25 फीसदी के बजाय 20 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। इसमें पांच फीसदी कमी का प्रस्ताव है। यानी पीटर इंग्लैंड के इम्पोर्टेड पैक की कीमत अब 35 रुपये कम हो सकती है। अब तक इसके लिए 249 रुपये चुकाने पड़ते हैं।

आयातित ब्लैंकेट्स हुए सस्ते

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशों से आने वाले ब्लैंकेट्स पर कस्टम ड्यूटी 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। यानी इस पर 15 फीसदी की कटौती की गई है। इससे विदेशी ब्लैंकेट की कीमत में कमी आएगी। यानी अब 7,000 रुपये के वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के लिए आपको 500 रुपये कम देने होंगे।

ओवरकोट भी हुआ सस्ता

सर्दियों में ओवरकोट पहनना भी अब सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में विदेशी ओवरकोट पर कस्टम ड्यूटी 25 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने की घोषणा की है। ज़ारा के ओवरकोट के लिए अब आपको 7990 रुपये के बजाय 7740 रुपये खर्च करने होंगे। यह कैल्कुलेशन लोकप्रिय ब्रांड की खुदरा कीमतों पर आधारित है।

पंकज वाधवानी

(अधिवक्ता एवं लॉ प्रोफेसर)
(लेखक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं)

नए भारत का दूरदर्शी बजट

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता एवं विधि व्याख्याता पंकज वाधवानी ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट बताया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एडवोकेट पंकज वाधवानी ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट है। बजट देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है, जो नए भारत की नींव रखेगा । ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा।

गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है बजट-संतोष वाधवानी

रक्षा बजट का 70 प्रतिशत घरेलू बाजार से क्रय करना इस बजट का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष

संतोष वाधवानी

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के संतोष वाधवानी (रत्न विशेषज्ञ) ने कहा है कि इस बजट में 80 लाख में मकान बनेंगे जो कि सीधे-सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक वरदान के रूप में साबित होंगे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब और मध्यम वर्ग को को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। वाधवानी ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से पहली बार इस केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का 70% घरेलू उत्पादों से क्रय करने का कहा गया है यह क्रांतिकारी कदम है और यही बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

महंगा पड़ेगा अपडेटेड आईटीआर फाइल करना, चेक करें कितना करना होगा भुगतान?

बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। टैक्स रिटर्न के नियमों में राहत देते हुए सरकार ने 2 साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कम टैक्स फाइलिंग की स्थिति में रिवाइस टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट के साल से दो साल तक खुली रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर में कुछ जानकारी देना भूल जाता है या फिर कोई जानकारी छूट जाती है तो वो उसे अगले 2 साल में सुधार या अपडेट कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा ,'ऐसी गलतियां दूर करने का मौका देने के लिए, मैं अतिरिक्त टैक्स के भुगतान पर टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने के लिए एक नए प्रोविजन का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अपडेटेड रिटर्न संबंधित असेसमेंट वर्ष के खत्म होने से दो साल के भीतर तक फाइल किया जा सकता है। इस कदम से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और कोर्ट के मामलों में भी कमी आएगी।' आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर्स को राहत जरूर मिलेगी लेकिन अतिरिक्त टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा।

आइए जानते हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा?

बजट डॉक्युमेंट्स में कहा गया है, 'अतिरिक्त इनकम पर ड्यू इंट्रेस्ट और टैक्स पर अतिरिक्त 25 से 50 फीसदी टैक्स टैक्सपेयर्स को चुकाना होगा। ऐसी अतिरिक्त आय की रिपोर्ट करते समय, टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।'' टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि ऐसी अतिरिक्त आय की रिपोर्ट करते समय, टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा।'' उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय ड्यू टैक्स और इंटरेस्ट के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान भी करना होगा। यानी जो टैक्सपेयर्स क्लीन रहना चाहते हैं, उन्हें ष्ठ्रँ फाइल करते समय भुगतान योग्य टैक्स और इंटरेस्ट के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त रकम देनी होगी, जो 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने पर 25 फीसदी या 24 महीने के भीतर 50 फीसदी होगी। बलवंत जैन ने कहा 'यह प्रस्ताव टैक्सपेयर्स के लिए सस्ता नहीं है।'

उन्होंने कहा कि एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न की शुरूआत ने टैक्सपेयर्स के मन में डर की भावना पैदा की है जो पूरी तरह टैक्स का भुगतान करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा ''चूंकि सरकार के पास उन करदाताओं को जिन्होंने अपनी आय पूरी तरह से घोषित नहीं की है या अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया उन्हें ट्रैक करने के लिए कोई बैंडविड्थ नहीं है। इसलिए वह टैक्सपेयर को क्लीन होने का मौका देने के लिए नया आइडिया लेकर आई है लेकिन इसके लिए अतिरिक्त कॉस्ट चुकानी होगी।'

सभी टैक्सपेयर्स के पास कर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पांच महीने की सीमित विंडो में अपने टैक्स रिटर्न को संशोधित करने का अवसर है अब अपडेटेड रिटर्न रिलेवेंट एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल की अवधि के भीतर दाखिल किया जा सकता है। बजट ज्ञापन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा आय का अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 में एक नया प्रावधान पेश किया जा रहा है, चाहे उसने संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए पहले रिटर्न दाखिल किया हो या नहीं।

देशभक्त नागरिक और सशक्त भारतः एक स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति के मायने

'देशभक्ति' यह शब्द सुनते ही एक देशभक्त नागरिक का तन मन रोमांच से भर जाता है, अपने देश के प्रति प्रेम से उसका मन सदैव भरा रहता है, लेकिन देशभक्ति असल में क्या है इसके बारे में वो जरा भ्रम की स्थिति में रहता है, जब कोई देश गुलाम होता है तो उस देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति मतलब देश की आजादी की लड़ाई पूर्णकालिक रूप से लड़ना होता है, गुलामी से आजादी पाना ही देशभक्ति होती है लेकिन स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद उन्हे समझ में नही आता कि अब तो हम आजाद हो गए है अब किससे लड़ना है, अब हमारे लिए देशभक्ति के मायने क्या है, और शनैः शनैः वो उदासीन होने लगता है, वैसे तो देशभक्ति की भावना कभी मरती नही है लेकिन किसी स्पष्ट उद्देश्य के अभाव में सुप्तावस्था में चली जाती है।

अपने देश के नागरिक होने के नाते हमारे मन में अपने देश के लिये अच्छी और बुरी दोनों तरह की विभिन्न भावनाएं निरंतर उमड़ती रहती है लेकिन इन सबमें सबसे सशक्त भावना होती है देशभक्ति की भावना । अपने देश से प्रेम करना, उसका सर्वोपरि सम्मान करना और सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति कहलाता है, एक सच्चा देशभक्त अपने देश को एक महान देश बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। एक देशभक्त नागरिक देश के प्रति समर्पित, साहसी और मजबूत इरादों वाला होता है । देशभक्ति विभिन्न रूपों में आती है और प्रत्येक नागरिक देशभक्ति की भावना को स्थायी रूप से अपनाए यह एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं। मेरे द्वारा सम्पन्न किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होना चाहिए। मुझे राष्ट्र विरोधी कार्य से स्वयम को दूर रखना चाहिये।

जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक झुकाव, आदि अनेकों प्रकार के विभिन्न छोटे-छोटे हिस्सो में बंटे हम भारतीय नागरिक जब भी देशभक्ति की बात आती है तो ना जाने कैसे हम सब एक हो जाते है, भारतीय हो जाते हैं, यह चमत्कार कैसे होता है यह कोई नही जानता, यह एक अद्भुत बात है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्त कहलाना पसंद करता है और देशद्रोही कहलाने की बजाय जीवन त्याग करना पसन्द करता है । सामान्यतया देश भक्ति से हमारा मतलब मिलिटरी (सेना) में भर्ती होने से होता है, सीमा पर युद्ध करने से होता है, पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने से होता है, चीनी सामान का बहिष्कार करने से होता है, इंग्लैंड से हमारा पुराना सामान वापस लाने से होता है, पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म देखकर तालिया बजाने से होता है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाते समय खड़े होने से होता है, एक आम नागरिक इससे या इसी तरह की अन्य बातों से परे जाकर देशभक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है ।

राजकुमार जैन
स्वतंत्र विचारक

हमें स्वतंत्र हुए लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं और अब हमें देशभक्ति को नए ढंग से परिभाषित करने के बारे में गंभीरता से सोच विचार करने की महती आवश्यकता है, हमें यह समझना होगा कि केवल सेना या पोलिस में या अन्य सुरक्षा एजेंसियों में काम करते हुए देश के दुश्मनों से संघर्ष करते हुए शहीद हो जाना ही देशभक्ति नहीं है, देशप्रेम प्रकट करने के लिए सैनिक बनाना ही एकमात्र उपाय नही है क्योंकि हर कोई तो सैनिक नही बन नही सकता। एक आजाद और सशक्त देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति के मायने क्या होना चाहिए इसके लिए एक विस्तृत सोच विचार की आवश्यकता है क्योंकि आजकल हम अपने निजी कामों मे इतने व्यस्त हैं कि हम अपने देश को सम्मान देना भूल गए हैं। किसी देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए उस देश की एकता और अखंडता अति महत्वपूर्ण है। कोई भी देश तभी उन्नति कर पाता है जब उस देश के नागरिक एकजुट हों। एकता के सूत्र में बंधे मजबूत देश को सम्पूर्ण विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है, देश के अंदरूनी विवाद व देश के नागरिकों का आपस में लड़ना, गृह कलह आदि देश के विकास में बाधा खड़ी करते हैं, देश को कमजोर करते हैं।

इस शब्द 'देश ॠ भक्ति' का वास्तविक अर्थ समझने के लिए पहले देश की परिभाषा को जानने का प्रयास करते है और उस सुपरिभाषित देश की भक्ति की बात बाद में करेंगे, एक देश क्या होता है, देश कैसे बनता है, कौन बनाता है देश को, इस तरह के कई सवाल है जिनके उत्तरों में छुपी है देश की परिभाषा , जैसे भगवान का मतलब कोई तस्वीर, मूर्ति या मंदिर या अन्य कोई इमारत नही होता है और उन प्रतीकों की पूजा का मतलब भक्ति नहीं होता है वैसे ही देश का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता और उसकी रक्षा का मतलब देशभक्ति नहीं होता है, जैसे घर बनता है घर में रहने वालों से उसी तरह देश बनता है देशवासियों से, देश के समस्त नागरिक मिलकर ही देश का निर्माण करते है, अच्छे नागरिक अच्छा देश बनाते है और बुरे देशवासी एक बुरे देश को परिभाषित करते हैं, मजबूत देशवासी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते है और कमजोर नागरिक एक कमजोर देश का, कोई देश कितना उन्नत है यह उस देश के नागरिकों के आचरण से जाना जाता है, तो देश मतलब हुआ उस देश के निवासी और उनका आचरण । आइये अब देशभक्ति की बात करते हैं, हम नागरिकों का एक दूसरे के प्रति सदव्यवहार देशभक्ति है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द का भाव रखना देशभक्ति है, नागरिकों का उत्थान ही देश का उत्थान है अतः एक दूसरे के उत्थान में मदद करना देशभक्ति है, उन्नत नागरिक ही उन्नत देश का निर्माण करते हैं अतः आपसी सहयोग से सबको उन्नत करना देशभक्ति है, देश का हर नागरिक वो जहां भी हो, जो भी दायित्व उसके पास हो वो अपना अपना कार्य पूर्ण सामर्थ्य और ईमानदारी से अन्य नागरिकों की बेहतरी का भाव रखकर करे यह देशभक्ति है । हम वो कार्य करे जिससे देश की उन्नति हो यह देशभक्ति है।

जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा का प्रतिदान दे यह देशभक्ति है, विद्यार्थी अपना चित्त अध्ययन में और ज्ञानार्जन में लगाये यह देशभक्ति है, एक व्यापारी अपना व्यापार ईमानदारी से करे ग्राहनों को उत्कृष्ट वस्तुओं की उपलब्धता उचित मूल्य पर निश्चित करे यह देशभक्ति है, एक ग्राहक बिना टेक्स का और निम्न गुणवत्ता के सामान का बहिष्कार करे यह देशभक्ति है, एक वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाये यह देशभक्ति है, वाहन में बैठी सवारियां वाहन चालक को नियम तोड़ने को प्रेरित ना करे यह देशभक्ति है, चुनाव के समय राजनेता मतदाता को प्रलोभन ना दें यह देश भक्ति है और हम बगैर भय या लालच के सही उम्मीदवार चुने यह देशभक्ति है, सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे या सत्यता को जाँचे अफवाहे ना फैलाये यह देशभक्ति है, सरकारी या गैरसरकारी कर्मचारी पूर्ण कुशलता और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे यह देश भक्ति है, उन विभागो या संस्थानो से सेवा प्राप्त करने वाले नागरिक अपना हित साधने के लिए, अपना काम बारी से पहले करवाने के लिए, गलत काम की सजा से बचने के लिए, सरकारी और गैरसरकारी संस्थानो में कार्य करने वाले कर्मचारियो को भ्रष्ट ना बनाए यह भी देशभक्ति है, इनसे उलट कार्य करने से देश कमजोर होता है और देश को कमजोर करने के कार्य को देशद्रोह भी कहा जा सकता है, बात कहने का मतलब यह है कि देश का हर नागरिक स्वयम को देशभक्त कह सकता है यदि वो अपना कार्य भलीभांति कर रहा है, चाहे वो एक सफाईकर्मी हो, टेक्नीशियन हो, दर्जी हो, नाई हो, प्लमबर हो, सरकारी या गैरसरकारी कर्मचारी हो, पायलट हो, डॉक्टर हो वकील हो, पानी पुरी का ठेला लगाता हो या चाय की गुमटी ही क्यों ना चलाता हो, अन्यथा कमजोर नागरिक एक कमजोर देश का ही निर्माण कर सकते हैं ।

आज हमें यह विचार करना चाहिए कि हम कैसा देश चाहते है, व्यापक सोच रखने वाले, मजबूत इरादे वाले, सुशिक्षित, चरित्रवान, बुद्धिमान, योग्य, सकारात्मक सोच वाले ईमानदार नागरिकों से बना एक सशक्त भारत या अयोग्य, बेईमान, कमजोर, लालची, धूर्त, अशिक्षित, आपराधिक सोच वाले भ्रष्ट नागरिकों से बना एक कमजोर राष्ट्र।

आईये आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान हम शपथ ले कि हम अपने कर्तव्य का पालन देशभक्ति की भावना से करेंगे और एक मजबूत और गौरवशाली भारत का निर्माण करेंगे, अपने बच्चो को एक अच्छा मनुष्य और उत्कृष्ठ नागरिक बनाएँगे जो आगे चलकर सशक्त भारत की नींव रखेंगे और भारत को उसका खोया हुआ गौरव पुनः लौटाकर विश्व का अग्रणी और सिरमौर देश बनाएँगे।

नवाचार एवं स्टार्टअप्स ही अर्थव्यवस्था के बूस्टर डोज़

डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी
मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स, इंदौर में प्रोफ़ेसर एवं समूह निदेशक की भूमिका में कार्यरत हैं।

नये भारत का महत्वाकांक्षी बजट आज सदन में पेश किया गया। जिसमें यह बताया गया कि पिछले छः महीनों में अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है और बजट 2022 में स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सरकार ने अधिक फ़ोकस किया है। एम. एस. एम. ई को मज़बूत बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर देने से नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्षेत्रीय विषमताओं में संतुलन लाने की आवश्यकता पर सरकार ने ज़ोर दिया है। पूर्व के आर्थिक लक्ष्यों को पूर्ण करने की पूरी तैयारी एवं इंडिया-100 की तैयारी को दर्शाता है यह बजट।मंत्रालयों में अति महत्व के मंत्रालयों को अधिक बजट एवं कम महत्व के मंत्रालयों को कम बजट से सरकार की दूरदर्शिता प्रतिलक्षित हो रही है। सेवा क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक है परंतु, पिछले बजटों में सेवा क्षेत्र के लिये कुछ अधिक नहीं किया गया।कुछ का कहना है कि राजकोषीय घाटा बढ़ना चिंता का विषय है परंतु एक मत ये भी कहता कि भारत को फ़िस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करना है क्योंकि 9.2इ का ग्रोथ अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे रहा है। भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अतः यह समय नवाचारों को बढ़ावा देने का है। सेमी कंडक्टर्स में आत्मनिर्भरता भारत को एक नयी ऊँचाई देने वाला है। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एवं ब्लाकचेन एनालिटिक्स के द्वारा नये भारत में शोध एवं आविष्कारों का सृजन तेज़ी से होगा।डिजिटल गेमिंग के क्षेत्र में नवाचार द्वारा भारी मात्रा में रोज़गार सृजन हित प्रयोग अभिनंदनीय हैं। युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग जनों के लिये यह एक कल्याणकारी बजट सिद्ध होगा। जहाँ एक तरफ़ इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस 2.0 को लेकर सरकार कटिबद्ध है वहीं दूसरी ओर मिनिमम गवर्नमेंट ऐंड मैक्सजिमम गवर्नेंस हेतु कृतसंकल्पित। चाहें वह रेलवे हेतु 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' की बात हो या फिर 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' ई-पासपोर्ट की सुविधा हो या फिर 2 लाख करोड़ की सहायता से एम. एस. एम. ई क्षेत्र का पुनर्निर्माण हो, व्यापक आत्मनिर्भरता को दर्शाते इस बजट में सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास दिख रहा है। सरकार ने ऐसे कल्याणकारी दूरदर्शी बजट के तैयार करने में काफ़ी होमवर्क किया होगा। इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा अगले पाँच वर्षों में 60 लाख रोज़गारों के सृजन का लक्ष्य एक व्यापक दृष्टिकोण है जो लंबे समय तक स्थाई रहेगा। कोरोना महामारी के चलते हेल्थकेयर के क्षेत्र में व्यापक इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट से हेल्थकेयर क्षेत्र मज़बूत बना है सरकार इस बजट के माध्यम से इसे और मजबूत बनाने को संकल्पित है। कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिये स्टार्टअप्स की आवश्यकता पर बल अर्थव्यवस्था के लिये सकारात्मक दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। आयल सीड (तिलहन) का इंपोर्ट बंद करने की योजना भारतीय किसान को संबल प्रदान करेगा। ग्रामीण भारत को सस्ती किफ़ायती ब्राडबैण्ड की सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार की संभावनाएँ बढ़ेंगी जो कहीं ना कहीं कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के लिये एक बूस्टर डोज़ होगा। आई.सी.टी सर्विसेज़, टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज़, सेज एरिया को निर्यात हेतु संबल प्रदान करना, डेटा सेंटर्स की स्थापना, मल्टी मॉडेल कनेक्टिविटी से रेलवे-सड़क,हवाई-जलमार्गों के विकास हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा नये भारत को विश्व गुरु भारत के रूप में अपनी भूमिका तय करने से नहीं रोक सकता।

बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब है?

सरस्वती पूजा के दिन बहुत से शुभ योग बन रहे हैं जो विद्यार्थियों, साधकों, भक्तों और ज्ञान चाहने वालों के लिए बहुत ही शुभ है. इस दिन सिद्ध नाम शुभ योग है जो देवी सरस्वती के उपासकों को सिद्धि और मनोवांछित फल देता है. इसके साथ ही सरस्वती पूजा के दिन रवि नामक योग भी बन रहा है, जो सभी अशुभ योगों के प्रभाव को दूर करने वाला माना जाता है. इन सबके साथ ही सरस्वती पूजा के दिन एक और अच्छी बात यह होगी कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले बुद्धि कारक बुध ग्रह अपने मार्ग में होगा. इसके साथ ही शुभ बुद्धादित्य योग भी प्रभाव में रहेगा. जानें मां सरस्वती की पूजा विधि, मंत्र, वंदना और आरती.

सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त

पंचमी तिथि प्रारंभ- 5 फरवरी तड़के 3 बजकर 48 मिनट से शुरू

पंचमी तिथि समाप्त- 6 फरवरी तड़के 3 बजकर 46 मिनट तक

सरस्वती पूजा विधि

- मां सरस्वती की प्रतिमा लाएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें.
- अब देवी सरस्वती को रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत चढ़ाएं.
- अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और अपनी नई किताबें, पेंसिल, पेन चढ़ाएं.
- मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें.
- हवन करें और आरती कर पूजा समाप्त करें.

पढ़ाई से जी चुराता है आपका बच्चा तो सरस्वती पूजा के दिन ये उपाय करें

देवी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है. हर साल सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी और शिक्षक ही नहीं ज्ञान, संगीत के उपासक भी पूरे मन से सरस्वती पूजा करते हैं. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है. हर साल माघ मास की पंचमी तिथि को यह बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है. इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी को है. इस दिन छात्र और शिक्षक मां सरस्वती की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से वाणी दोष और पढ़ाई में मन न लगने जैसी बच्चों की समस्याओं का समाधान हो सकता है.

सरस्वती देवी ने मौन संसार में भरी वाणी

धार्मिक शास्त्रों में सरस्वती माता के बारे में ऐसा लिखा गया है कि मौन संसार में उन्होंने ही वाणी भरी. बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती हाथ में वीणा, पुस्तक और माला लिए हुए वर-मुद्रा में सफेद कमल पर विराजमान प्रकट हुई थीं. जैसे ही उन्होंने वीणा से मधुरनाद छेड़ा, समस्त जीव-जन्तुओं को वाणी प्राप्त हो गई. जलधारा में कोलाहल और हवा में सरसराहट होने लगी. मौन संसार में वाणी भरने वाली देवी सरस्वती ही हैं. उस दिन से ही देवी सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाने लगा.

सरस्वती पूजा करने से मुर्ख भी बन जाता है विद्वान

बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि ज्ञान और वाणी की देवी होने के कारण माता सरस्वती की उपासना करने वाला मूर्ख भी विद्वान बन जाता है. यदि किसी बच्चे की वाणी से जुड़ी कोई समस्या है तो वह भी दूर हो सकती है. ज्योतिष के अनुसार यदि बच्चे में किसी तरह का वाणी दोष है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो बसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से बच्चे की परेशानी दूर हो सकती है. बच्चे का मन पढ़ाई में न लग रहा हो या बच्चे को वाणी दोष की परेशानी हो तो बसंत पंचमी के दिन क्या उपाय करें जान लें.

वाणी दोष दूर करने के लिए ये उपाय करें

बसंत पंचमी के दिन बच्चे के वाणी दोष के लिए उपाय कर सकते हैं. यदि किसी बच्चे को वाणी दोष है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर की मदद से 'ऐं' लिख दें. ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चे की जुबान ठीक हो सकती है.

बच्चा पढ़ाई से जी चुराता हो तो ये उपाय करें

- **बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता. हर वक्त पढ़ाई से जी चुराता है तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को हरे रंग फल अर्पित करना चाहिए.**
- **बच्चे के स्टडी रूम में माता सरस्वती का एक चित्र रखें और बच्चे को पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माता को हाथ जोड़ कर प्रणाम करने के लिए कहें.**
- **सरस्वती पूजा के बाद बच्चे की जीभ पर शहद से ॐ बनाने से बच्चे की बुद्धि में वृद्धि होती है.**

गुप्त नवरात्रि में कर लीजिए 10 शुभ उपाय

इस बार माघ गुप्त नवरात्रि पर 2 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी। घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7.10 मिनट से सुबह 08.02 मिनट तक है। इस समय घट स्थापना के साथ ही गुप्त नवरात्रि के दिन आजमाएं यह शुभ उपाय

1. गुप्त नवरात्रि का सटीक उपाय- गुप्त नवरात्रि के दिन मां दुर्गा और महाविद्याओं का स्मरण करते हुए एक स्वच्छ, नया, सुंदर सजा हुआ मिट्टी का घड़ा लें। उसमें सप्त धान के थोड़े से दाने, 1 रुपए का या चांदी का सिक्का डालें। फिर गंगा जल मिश्रित पानी उसमें भरें। कलश के भीतर एक-एक सुपारी, पूजा बादाम और हल्दी की गांठ भी डालें। अब इस पानी पर थोड़ा-सा कुमकुम, अबीर और चावल छिड़कें। अब इसें दीये से ढंक दें। इस दीये पर छोटा पूजा नारियल रखें। नारियल पर नाड़ा बांधकर इस कलश की विधिवत पंचोपचार पूजा करें। कलश के सामने हाथ जोड़ कर, आंखें बंद कर प्रतिदिन की महाविद्या का स्मरण करें और अपनी गुप्त मनोकामना मन ही मन देवी से व्यक्त करें। जब पूजन से उठें तो आसन को प्रणाम कर आसन साथ में उठाएं।ऐसा 9 दिन की गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन करें। नौवें दिन कलश का जल अपने ऊपर और पूरे घर में छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी, पीपल या किसी भी पवित्र पौधे में अर्पित करें। अगर संभव हो तो यह जल नदी या स्वच्छ सरोवर में भी बहा सकते हैं। कलश की पूजा सामग्री में से निकला सिक्का अपने पास रख लें, शेष सभी विसर्जित कर दें। कलश उठाने से पहले अंतिम दिन 108 बार अपनी कामना बोलें।

2. यदि आप बच्चे की बुरी नजर से रक्षा करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा का निरंतर जप करना चाहिए और बच्चे के बाएं पैर पर बजरंग बली को चढ़ाया काजल और माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाना चाहिए।

3. यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे है तो गुप्त नवरात्रि में भैरव बाबा मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। नौकरी प्राप्ति में निश्चित रूप से यह उपाय सहायता करेगा।

4. गुप्त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।

5. सर्वविघ्न दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल से दीया जलाएं तथा अधिक से अधिक 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें।

6. हर तरह के सुख, समृद्धि, सफलता, खुशी, आनंद और प्रेम के लिए अपने मंदिर में शिव-पार्वती की एक मूर्ति स्थापित करें और इस मंत्र का 5 बार जाप करें। ॐ शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय, पुरुषार्थ चतुष्ठाय लभाय च पति मे देहि कुरु कुरु स्वहा।

7. गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक इस मंत्र का जप करें। 'सब नार करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीर्ति'। इससे पति-पत्नी के बीच का तनाव कम होता है। घी की 108 आहुति दें। बाद में जब भी आवश्यकता हो 21 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए।

8. गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का पूजन आधी रात को की जाती हैं। अतः सुबह के पश्चात रात्रि में गुप्त रूप से माता की अराधना करें।

9. आर्थिक लाभ के लिए, गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक पीपल पेड़ के पत्ते पर राम का नाम लिखें और उन्हें हनुमान मंदिर में अर्पित करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

10. हमेशा स्वस्थ रहने के लिए, 108 बार मंत्र- 'ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा श्यामा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।' का जप करें। यह मंत्र आपकी अनेक बीमारियों को दूर कर स्वस्थ होने में सहायता करता है।

सशक्तिकरण : मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 से मिलेगी महिलाओं को मजबूती

आम बजट में महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को नया रूप दिया है। वित्तमंत्री ने दो लाख आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की घोषणा की है। 'सक्षम आंगनबाड़ी' और पोषण-2.0 के लिए 20,263 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। इससे प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर परिवेश मिलेगा।सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत शिशुओं का पोषण बढ़ाने, शिशुओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उसकी डिलीवरी पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 'मिशन शक्ति' के लिए 3,184 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन हुआ है, जबकि 2021-22 में इसके लिए 3,109 करोड़ दिए गए थे। 'मिशन वात्सल्य' के लिए 1,472 करोड़ आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 900 करोड़ रुपये था। सीतारमण बोलीं, 'अमृत काल' ने नारी शक्ति के महत्व को पहचाना है।

इन योजनाओं में भी लाभ मिलेगा

बजट में लाखों नई नौकरियां सृजित करने की घोषणा की गईं, जिससे महिलाओं को भी फायदा होगा।

पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकान से गांवों-शहरों की महिलाओं का घर का सपना साकार हो सकेगा।

डाकघरों में एटीएम की व्यवस्था होने से गांवों की महिलाओं को भी सुविधा मिल सकेगी।

कट, पॉलिश डायमंड और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान। महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा।

एल्युमिनियम सेक्टर में छाया कोयले का संकट

15 दिन की सीमा की जगह बचा सिर्फ 3-4 दिन का स्टॉक

देश में एक बार फिर कोयले की कमी का असर देखने को मिल रहा है. हालांकि इस बार मुश्किल में एल्युमीनियम सेक्टर है. दरअसल इंडस्ट्री ने सरकार को कहा है कि उनके कैप्टिव पावर प्लांट में निर्धारित सीमा से काफी कम समय का कोयला बचा है और आपूर्ति नहीं हुई तो संयंत्र बंद हो जायेंगे जिससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. इंडस्ट्री के मुताबिक अगस्त से ही कोयला पाने में समस्या हो रही थी लेकिन अब स्थितियां गंभीर हो गई है. फिलहाल अक्टूबर में बिजली सेक्टर में कोयले की किल्लत के बाद से बिजली प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की सप्लाई हो रही है और उनका स्टॉक सुधर गया है हालांकि नॉन रेग्युलेटेड सेक्टर के लिये परेशान बढ़ गई है.

एल्युमीनियम सेक्टर के कैप्टिव प्लांट पर बंदी का खतरा

भारतीय एल्युमिनियम संघ (एएआई) ने सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए कहा है कि एल्युमिनियम क्षेत्र के तहत (कैप्टिव) बिजली संयंत्रों के पास फिलहाल तीन-चार दिन का ही कोयला भंडार बचा है जिससे बंदी का खतरा मंडरा रहा है. एल्युमिनियम उद्योग ने आर्थिक रूप से कामकाज को सुचारू रुप से चलाने के लिए कम-से-कम 25-30 कोयला रैक प्रतिदिन मुहैया कराने की मांग सरकार से की है. एएआई ने कोयला सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि बिजली संयंत्रों को पेश आ रही कोयले की किल्लत को तत्काल दूर करने के कदम उठाने की जरूरत है. संगठन ने कहा, ''एल्युमिनियम उद्योग के खुद के इस्तेमाल वाले बिजली संयंत्रों (सीपीपी) के पास सिर्फ तीन-चार दिन का ही कोयला भंडार रहता है, जबकि इसकी निर्धारित सीमा 15 दिनों के इस्तेमाल लायक कोयले की है.''एएआई ने कहा कि कोयले की उपलब्धता बेहतर होने के बावजूद गैर-नियमित क्षेत्रों के लिए कोयला की उपलब्ध नहीं होना चिंता का एक बड़ा मुद्दा है. अगस्त, 2021 से ही गैर-नियमित क्षेत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

आपूर्ति की जकड़न, जियोपोलिटिकल तनावों पर कच्चा तेल उच्च स्तर पर

एजेंसी

पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ आपूर्ति की निरंतर कमी के कारण लगभग एक वर्ष में अपने सबसे बड़े मासिक लाभ के लिए तेल की कीमतों में सोमवार को उच्च कारोबार हुआ। क्रूड वायदा 0.6% बढ़कर 87.33 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि ब्रेंट अनुबंध 0.6% बढ़कर 89.06 डॉलर हो गया। दोनों बेंचमार्क ने शुक्रवार को अक्टूबर 2014 के बाद से अपना उच्चतम स्तर दर्ज किया, और इस महीने लगभग 15% की बढ़त हासिल कर रहे हैं, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे अधिक है।

यूएस गैसोलीन आरबीओबी फ्यूचर्स 1.1% बढ़कर 2.5655 डॉलर प्रति गैलन हो गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन के साथ सीमा पर रूस की सेना के निर्माण पर चर्चा करने के लिए सोमवार को बैठक करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस के साथ परिषद में एक देश जो वीटो रखता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी।

रूस और पश्चिम यूक्रेन के लिए मास्को के इरादों पर कई हफ्तों से विवाद में हैं, एक तथ्य जो कच्चे बाजार को बढ़ावा दे रहा है, रूस यूरोप को अपनी प्राकृतिक गैस आपूर्ति को बाधित कर सकता है, अगर स्थिति हिंसक हो जाती है और पश्चिम प्रतिबंध लगाता है। सामान्य आपूर्ति जोखिम प्रीमियम को जोड़ते हुए, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसने यमन के हौथी द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया था क्योंकि खाड़ी राज्य ने इस तरह की पहली यात्रा में इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग की मेजबानी की थी।

यह सकारात्मक स्वर बुधवार को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों की बैठक से पहले जारी रहने की संभावना है, भविष्य के उत्पादन स्तरों पर चर्चा करने के लिए ओपेक + के रूप में जाना जाने वाला समूह। समूह को प्रति माह आउटपुट कोटा में प्रतिदिन 400,000 बैरल की सावधानीपूर्वक वृद्धि की अपनी रणनीति के साथ रहने की उम्मीद है, पिछले साल अगस्त के बाद से यह एक रुख है, यहां तक कि कई सदस्यों ने अपने कोटा को पूरा करने के लिए संघर्ष किया है। इसके परिणामस्वरूप मजबूत पोस्ट-महामारी की रिकवरी को देखते हुए तंग इन्वेंट्री हुई है। इसके अतिरिक्त, बेकर ह्यूजेस के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी ड्रिलर्स ने आपूर्ति की जकड़न और उच्च कीमतों के बावजूद उत्पादन का समर्थन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन में वृद्धि के बावजूद सतर्क गति से तेल रिग जोड़ना जारी रखा है।

अमेरिका ने पिछले सप्ताह में चार तेल रिग जोड़े, जबकि गैस की खोज के लिए एक और दो रिग जोड़े गए, 28 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए कुल रिग संख्या (तेल और गैस संयुक्त) को 610 तक ले गए। 'अभी भी पूर्व-कोविड स्तरों से काफी नीचे है। लगभग 683, यहां तक कि NYMEX WTI पूर्व-कोविड मूल्य स्तरों से ऊपर आराम से ट्रेड करता है, 'ING ने एक नोट में कहा।

उद्योग मंत्री ने जताया भरोसा

मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल कर सकते हैं 400 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य

नई दिल्ली । एजेंसी

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उम्मीद जताई है कि देश इस वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल कर सकता है. इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार दुनिया भर देशों के साथ कारोबारी समझौते करने की कोशिश कर रही है जिससे देश के उद्योगों को नये बाजार मिलें और निर्यात की रफ्तार और बढ़ाई जा सके. चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में भारत से निर्यात 335 अरब डॉलर को पार कर चुका है. खास बात ये है कि ओमीक्रॉन का खतरा कम होने के साथ जनवरी में निर्यात में तेज बढ़त देखने को मिली है। लोक सभा में दिये गये एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 400 अरब डॉलर के निर्यात करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार दूसरे देशों के साथ कारोबार को बढ़ाने के लिये यूएई, ईयू, कनाडा जैसे देशों के लिये कारोबारी समझौतों पर बात कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के साथ लगभग सभी कमोडिटी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही जिससे इनसे जुड़े सेक्टर में दबाव बना हुआ है. हालांकि अंतराष्ट्रीय बाजारों में तैयार उत्पादों की कीमतें भी इसी अनुपात में बढ़ रही हैं ऐसे में निर्यातकों को नुकसान नहीं हो रहा है. पीयूष गोयल ने कहा कि लगातार 10 वें महीने देश से निर्यात 30 अरब डॉलर के ऊपर ही रहा और देश वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में 334 अरब डॉलर के निर्यात का स्तर हासिल कर चुके हैं।

अनंत सेवा फाउंडेशन का प्रोजेक्ट डिग्निटी 2.0 ग्रामीण क्षेत्रों के 1000 गरीब परिवारों की करता है मदद

कोलकाता। एजेंसी

अनंत सेवा फाउंडेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आपदा राहत के क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के लिए काम करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट, ने हाल ही में अपनी परियोजना डिग्निटी को फिर से शुरू किया, जिसके तहत यह ग्रामीण गरीबों को लड़ने के लिए आराम प्रदान करता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कंबल वितरण कर सर्दी की ठिठुरन पैलेन, गोसाबा , खोलाघाटा , अमरावती , बक्खाली , पंचेर की गतिविधि से एक हजार (1000) परिवार लाभान्वितघेरी,झारग्राम,मालेकनी गूमती,जोगेशगंज-सभी दूरस्थ और अल्पविकसित गांव। पहल पर टिप्पणी करते हुए, निदेशक, कौशिक सिन्हा ने कहा, ' 2020-21 में, हमने अम्फान चक्रवात के पीड़ितों की मदद करने की पहल की, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। इस साल, हमारा ध्यान ' यास चक्रवात' के पीड़ितों के साथ जुड़ने पर था, जिसने दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। हमें उनकी मदद करने में खुशी हो रही है और

परामर्श और दवाओं का विस्तार करने के लिए जल्द ही इन क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना है।' अनंत सेवा ग्रामीण गरीबों को समानता, सम्मान और सशक्तिकरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड वेव 2 के दौरान परियोजनाओं जैसे कि मुफ्त चिकित्सा परामर्श, कोविड प्रभावित परिवारों को मुफ्त भोजन, कोविड मृतक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रायोजन और सामुदायिक टीकाकरण अभियान ने बहुत सद्भावना अर्जित की। शिक्षा में अनंत सेवा की प्रमुख परियोजना - विद्यासेवा छात्रवृत्ति जिसके तहत संगठन ने कमजोर आय वाले परिवारों की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति की पेशकश की, देशभर के छात्रों को एक उज्जवल भविष्य की तलाश में मदद की।

एपीएसईज़ेड ने वित्त वर्ष 22 के 9 महीनों में कार्गो वॉल्यूम में 22% और कुल राजस्व में 35% वृद्धि दर्ज की

अहमदाबाद। भारत में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी और विविधतापूर्ण अदाणी पोर्टफोलियो के एक हिस्से,अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ('एपीएसईज़ेड'), ने आज तीसरी तिमाही और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त नौ महीनों के अपने परिणामों की घोषणा की।

वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही में, अदाणी पावर मुंद्रा, जीजीपीएल जैसे प्रमुख आईपीपी द्वारा और कम ट्रेडिंग कोयले की वॉल्यूम के कारण कोयले के कम आयात के कारण कार्गो वॉल्यूम कम हो गया था, जो उच्च कमोडिटी की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के कारण प्रभावित हुआ था। बिजली की बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर कीमतों में नरमी के कारण वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में कोयले की मात्रा में सुधार होने की संभावना है।

एपीएसईज़ेडके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक, श्री करण अदाणीने कहा कि 'एपीएसईज़ेडने महामारी की अवधि के दौरान जबरदस्त लचीलापन (रीजिलियंस) दर्शाया था।2020 में जो सीख हमें मिली,

उसने हमें तूफान का सामना करने में मदद की और हमारी परिचालन विशेषज्ञता ने हमें अपना विस्तार जारी रखने की अनुमति दी। पश्चिमी तट पर स्थित हमारे बंदरगाहों के साथ, 2021 में दो बंदरगाहों - भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम और गंगावरम – को शामिल करने से हमारी अखिल भारतीय उपस्थिति को मजबूती मिलना जारी रहा। केरल में विझिंजम का हमारा निर्माणाधीन बंदरगाह, श्रीलंका के कोलंबो में हमारे नए टर्मिनल के साथ, दक्षिण-पूर्व एशिया में एक नए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा।' श्री करण अदाणी ने बताया कि 'हमारी कार्बन ऑफसेटिंग, मैंग्रोव वनीकरण और स्थलीय वृक्षारोपण, के साथ ही अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर हमारे व्यापक ध्यान देने का अर्थ है कि एपीएसईजेड 2025 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने और दुनिया की सबसे टिकाऊ पोर्ट्स कंपनी बनने की राह पर है।' अपने ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी मॉडल को मजबूती प्रदान करने में अदाणी ग्रुप की प्रगति हासिल करना इस तथ्य को मान्यता देता है कि परिवहन बुनियादी ढांचा अतना ही अहम कार्य करता है, जितना कि बिजली करती है। इस परिवहन यूटिलिटी मॉडल को रेल नेटवर्क में विस्तार और ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग क्षमता के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में अधिक निवेश करके बढ़ाया गया था। अदाणी ग्रुप विकास की गति को तेज करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण में निवेश करना जारी रखेगा।

क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए इस पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा रहे, बोले वित्त सचिव

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल करेंसी को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30इ की दर से कर लगा रहे हैं। इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संसद में मंगलवार को पेश किए गए आम बजट का जोर गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थाई समाधानों से जोड़ने पर है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से वर्ष 2022-23 के आम बजट पर आयोजित कार्यक्रम ''आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था'' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो।

उधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार अपना ही गुणगान करते रहने एवं आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने में लगी है। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि न तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद गंगा साफ हुई, न ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां आतंकी हिंसा में कमी आई, उल्टे देश भर में महंगाई और बेरोजगारी ने कोविड के कारण पहले से ही परेशान आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। जबकि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि देश बदल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल मिशन के तहत अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पर्याप्त पीने का पानी आएगा, कृषि के लिए खेतों में पानी आएगा।''

नई दिल्ली में बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- कल निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। बीते 7 वर्षों में जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है।

बोले- देश इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। कोरोना कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां टर्निंग प्वाइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया जो हम देखने वाले हैं, वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। कहा- बीते 7 वर्षों में जो नीतियां बनी, पहले की नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। बजट में यह साफ दिख रहा है।

संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किये जाने के एक दिन बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछल गया तथा निफ्टी 17,650 को पार गया। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 416.56 अंक या 0.71 प्रतिशत बढ़कर 59,279.13 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 117.95 अंक या 0.67 फीसदी की तेजी के साथ 17,694.80 पर आ गया।

डिजिटल रूपी के अलावा बाकी कोई नहीं है लीगल टेंडर

डिजिटल करंसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होगी और इसमें कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकेगा। यह पैसा आरबीआई के पास होगा, लेकिन इसकी प्रकृति डिजिटल रहेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई डिजिटल रूपी एक लीगल टेंडर होगी। इसके अलावा बाकी कोई भी डिजिटल करंसी लीगल टेंडर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह कभी लीगल टेंडर बनेंगी भी नहीं।

क्रिप्टो में पैसा डूबा तो सरकार नहीं होगी जिम्मेदार

उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि इसे सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या आपका पैसा डूब जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि क्रिप्टो में निवेश से आपको नुकसान भी हो सकता है और यहां ये समझना जरूरी है कि इसके लिए सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

मतलब कभी लीगल नहीं होगा बिटकॉइन

टीवी सोमनाथन की बात से यह साफ हो जाता है कि रिजर्व बैंक की तरफ से जारी डिजिटल रूपी के अलावा कोई भी डिजिटल करंसी लीगल टेंडर नहीं है, ना ही कभी होगी। यानी सरकार का अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वह भविष्य में भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी को लीगल करे। हालांकि, सरकार ने इस पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि उस पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।